जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 25 प्रभात बीकानेर, गुरूवार 25 दिसम्बर, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रू.

पड़ोसी देशों के ''स्टेटस'' (हैसियत) में भारी अंतर, अमधुर संबंध होने का कारण होता ही है

पर, बाँग्लादेश में इस भावना पर अब पाकिस्तान व रूढ़िवादी तत्वों का काबिज होना जरूर गहरी चिंता पैदा करता है

- इस पूरे प्रकरण में, थोड़ा ढांढस इस बात से बनता है कि दीपू चंद्र दास की बेरहम, पाशविक हत्या से इतना हड़कंप मचा कि बाँग्लादेश की अंतरिम सरकार को रक्षात्मक मुद्रा में आना पड़ा व उसे दास के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा करनी पड़ी और परिवार को सहायता देने की बात भी कही।
- अंतरिम सरकार ने हत्या को अंजाम देने वालों को गिरफ्तार कर, दंड देने की घोषणा भी की तथा चौदह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है।
- पर, यह भी सच है कि जिस तेजी से सामुदायिक हिंसा फैली, आगजनी हुई और हिंदुओं पर आक्रमण हुआ, इससे साफ उजागर हुआ कि देश में अस्थिरता और कानून व्यवस्था का नितांत अभाव है, जिसका रूढ़िवादी ताकतें पूरा लाभ उठा रही हैं।
- पड़ोसी राज्य में फैलती हिंसा व अस्थिरता की भारत अनदेखी नहीं कर सकता। क्योंकि, भारत में शांति व स्थिरता के लिए बाँग्लादेश में ''अस्थिरता'' समाप्त होना जरूरी है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर। बांग्लादेश में हाल में हुई घटनाओं और एक हिंदू युवक पर किए गए अमानवीय अत्याचार और उसकी मौत ने दोनों पड़ोसी देशों के कूटनीतिक संबंधों को बिगाड़ दिया है। इस मौत के बाद दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने अपने आप ही लोग इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

दूसरी ओर, ढाका में एक बांग्लादेशी युवा नेता की मौत के बाद भारत के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। ढाका में भारतीय उच्चायोग के खिलाफ नारेबाज़ी की गई और भारत के उत्तर-पूर्व से सटे चिटगांव बंदरगाह शहर में भारतीय उच्चायोग पर भीड़ ने हमला कर दिया।

बांग्लादेश में अचानक फैली व्यापक हिंसा उस देश की ज़मीनी हकीकत और उसकी अंदरूनी अस्थिरता को दिखाती है। बांग्लादेश में लगातार बने हुए संकट को भारत नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता है और इस पर आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकता। भारत की अपनी सुरक्षा भी बांग्लादेश की स्थिरता पर निर्भर करती है।

दोनों देशों ने औपचारिक रूप से कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखे हैं, लेकिन संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। भारतीय लोगों की अचानक और कड़ी प्रतिक्रिया के कारण बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा और कुछ सहायता की घोषणा करनी पड़ी।

सरकार अब अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सज़ा देने का वादा कर रही है। इस मामले में शामिल पाए गए करीब चौदह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि माना जा रहा है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं।

लेकिन घटनाओं के इस सिलसिले ने पहले से ही नाज़ुक और असहज चल रहे पड़ोसी संबंधों को और खराब कर दिया है, जहाँ आम लोगों के बीच भारत-विरोधी भावनाएँ पहले से मौजूद

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सिद्धार्थ महाजन जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त बने

जयपुर (कासं)। राज्य सरकार ने बुधवार शाम आदेश जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के पांच अधिकारियों का तबादला किया। इस आदेश के मुताबिक, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे सिद्धार्थ महाजन को जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) आयुक्त बनाया गया है। इस पद पर पूर्व में कार्यरत आयुक्त आनंदी को सहकारिता विभाग राजस्थान की रजिस्ट्रार और शासन सचिव के पद पर लगाया गया है। इसके साथ ही जयपुर

- आनंदी का सहकारिता तथा राकेश शर्मा डीआईपीआर आयुक्त पद पर तबादला।

विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त आयुक्त की सेवाएं दे रहे राकेश शर्मा को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान (डी.आई.पी.आर.) के आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई।

आईएएस मंजू राजपाल को कृषि-उद्यानिकी एवं पंचायतीराज (कृषि) विभाग राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव पद पर लगाया है। राजस्थान राज्य बीज निगम लि. के अध्यक्ष का जिम्मा भी मंजू राजपाल ही संभालेंगी। इसी प्रकार बाबूलाल गोयल को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में सचिव बनाया गया है। राज्य सरकार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उद्धव व राज के एक होने की प्रक्रिया अचानक नहीं फलीफूत हुई

गत विधानसभा चुनाव में और स्थानीय निकाय चुनावों में दोनों को मुँह की खानी पड़ी थी, अतः दोनों महसूस कर रहे थे कि एक होंगे तभी जीवित रहेंगे

- इस प्रक्रिया में, भाजपा ने ''कैटलिस्ट'' (उत्प्रेरक) की भूमिका अदा की, एक से पाँचवी कक्षा तक हिंदी को स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करके।
- उद्धव व राज को मौका मिल गया और वो एक मंच पर दिखे, ''मराठी मानुष'' की बात करने के लिए।
- अगर उद्धव व राज ''मिलन'' सार्थक साबित हुआ, मुंबई म्युनिसिपल चुनाव में तो शरद पवार व अजित पवार भी इस ''थीम'' का अनुसरण करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
- साथ ही, उद्धव ठाकरे ने भी शिंदे शिव सेना के असंतुष्ट तत्वों से बातचीत शुरु कर दी हैं, ''घर वापसी'' के लिए।

-श्रीनंदन झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 दिसंबर। बृहन्नमुम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (बीएमसी) सहित, 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होने जा रहे हैं और अब तक अलग-अलग चल रहे चचेरे ठाकरे भाइयों, उद्धव और राज ठाकरे, ने हाथ मिला लिया है, पर क्या इससे महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया मोड़ आएगा?

लम्बे समय तक लड़ते रहे इन चचेरे भाइयों के एक साथ आने की संभावना की खबरें जून से ही शुरु हो गई थीं, जब कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने के महायुति सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए उद्धव और राज एक ही मंच पर दिखाई दिए थे। हालांकि भाजपा नेताओं ने यह सफाई देने की कोशिश की थी कि हिंदी सम्बन्धी फैसले को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, लेकिन दोनों ठाकरे भाइयों ने इस मुद्दे को ''मराठी मानूस'' के नारे के साथ जोड़ दिया और अपने राजनीतिक भविष्य को फिर से मजबूत करने के मकसद से पूरी तरह भुना लिया।

पिछले विधानसभा चुनावों में शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, दोनों को करारी हार मिली थी। हाल ही में, 286 नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भी दोनों दलों को ऐसा ही झटका लगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह नई एकजुटता ठाकरे भाइयों की किस्मत फिर से बदल पाएगी?

इसका जवाब तो 16 जनवरी को तब मिलेगा, जब नगर निगम चुनावों के नतीजे आएंगे, लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा है कि उद्धव और राज के साथ आने से उन्हें लड़ने का एक नया और बेहतर मौका जरूर मिला है।

इस मेल-मिलाप का सीधा असर यह हुआ है कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस अलग-थलग पड़ गई है और अब वह निगम चुनाव अपने दम ही पर लड़ेगी। बीएमसी चुनावों में ठाकरे भाइयों की सफलता के आधार पर, आगे और भी बदलाव हो सकते हैं। मसलन, एनसीपी के शरद पवार और अजित पवार गुटों के एक होने की संभावना पर भी चर्चा चल रही है। वहीं, उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट की शिवसेना के असंतुष्ट नेताओं से भी घर वापसी कर, मूल शिवसेना में शामिल होने की अपील की है। कुल मिलाकर, राज्य की राजनीति में नए सिरे से शक्ति संतुलन बनने की संभावनाएँ खुल गई हैं।

भाजपा ने इस घटनाक्रम को ज़्यादा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मैं दिल्ली में दो दिन भी रहता हूँ तो इन्फैक्शन हो जाता है'

केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के प्रदूषण पर रोष जताया और पूछा, आखिर दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों है

- उन्होंने कहा, मैं परिवहन मंत्री हूँ, 40 प्रतिशत प्रदूषण तो हमारे कारण है, जीवाश्म ईंधन (पैट्रोल डीज़ल आदि) के कारण है, हम हर साल 22 लाख करोड़ रूपए का पैट्रोल डीज़ल आयात करते हैं, यह कैसा राष्ट्रवाद है, क्या हम वैकल्पिक ईंधन और बायो फ्यूल का इस्तेमाल कर आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते हैं।
- गडकरी ने पत्रकार उदय मुहरकर की किताब ''माय आईडिया ऑफ नेशन फर्स्टः रीडिफाईनिंग अनएलॉयड नैशनलिज़्म'' के विमोचन के दौरान यह बयान दिया।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर। दिल्ली की जहरीली हवा पर सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर से भी कड़ी टिप्पणियाँ आई हैं। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में दो दिन रहने से उन्हें इन्फ्रैक्शन हो जाता है।

वरिष्ठ पत्रकार उदय महुरकर की किताब 'माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट: रीडिफाइनिंग अनएलायड नेशनलिज़्म' के विमोचन के अवसर पर गडकरी ने कहा कि आज का सबसे बड़ा राष्ट्रवाद यह होगा कि हम देश के निर्यात को बढ़ाएं और आयात को घटाएं। उन्होंने कहा, ''मैं (दिल्ली में) केवल दो दिन रहूं, तो मुझे संक्रमण हो जाता है। दिल्ली प्रदूषण से क्यों जूझ रही है?''

उन्होंने कहा, ''मैं परिवहन मंत्री हूं, 40 प्रतिशत प्रदूषण हमारे कारण है... जीवाश्म ईंधन के कारण। हम 22 लाख करोड़ रुपये जीवाश्म ईंधन आयात करने और प्रदूषण बढ़ाने पर खर्च कर रहे हैं। यह किस तरह का राष्ट्रवाद है?'' उन्होंने अफसोस जताया कि लोग ईको-फ्रेंडली प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने प्रश्न किया, ''क्या हम वैकल्पिक ईंधन और जैव ईंधन को काम में लेकर आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते?''

एक अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणी में गडकरी ने कहा कि यह कहना गलत है कि हर मुस्लिम आतंकवादी होता है। उन्होंने कहा, इस चीज का वर्गीकरण या ग्रेड-निर्धारण होना चाहिये कि कोई व्यक्ति कितना कट्टर तथा जहरीला है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम हमारे आदर्श हैं; डॉ. कलाम जैसे लोगों की संख्या बढ़ानी होगी। शिक्षा को उनके पास

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरकार ने किया बांके बिहारी मंदिर का अधिग्रहण

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 दिसंबर। 22 दिसंबर, 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट एक्ट को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया। मथुरा जिले के वृंदावन का बांक बिहारी मंदिर भारत के सबसे पवित्र कृष्ण मंदिरों में से एक है और अब यह मंदिर सरकार के नियंत्रण में आ गया है।

हिंदू राइट्स ऐक्टिविस्ट्स का

- यूपी सरकार ने यह अधिग्रहण बांके बिहारी टैम्पल ट्रस्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत किया है, हालांकि हिंदू एक्टिविस्ट इसे धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन बता रहे हैं।

कहना है कि यह सरकार का हस्तक्षेप है, धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन है, एक खतरनाक मिसाल की शुरुआत है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल-प्रियंका-सचिन की तिकड़ी 2029 के लिए?

वेणुगोपाल द्वारा ''ऑपरेशन केरल'' की जिम्मेवारी के लिए उन्हें भेजने का आग्रह करने से, तिकड़ी की चर्चा जोरों से शुरु हुई एआईसीसी में

- अशोक गहलोत, अजय माकन और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने रिक्त संगठन महासचिव पद पाने की पूरजोर इच्छा जताई, लेकिन भाजपा, द्वारा 45 वर्षीय नितिन नबीन को पार्टी अध्यक्ष बनाने के बाद कांग्रेस की मजबूरी हो गई है कि संगठन महासचिव की जिम्मेवारी युवा नेता को दी जाए। अतः सचिन पायलट का नाम पुराने नेताओं को पसंद आ रहा है।
- पुराने नेता, ''जय जगत'' नेताओं के पुराने लेफ्ट-ऑफ-सैंटर चिंतन को अब पूरी तरह समय संगत नहीं मानते। इन ''जय जगत'' नेताओं में मीनाक्षी नटराजन, अल्लावेरू, शशिकांत सेन्थिल, सचिन राव, भंवर जितेन्द्र सिंह प्रमुख हैं।
- माना जा रहा है कि कांग्रेस कोई भी नया काम करने से पहले मलमास, जो 14 जनवरी को समाप्त हो रहा है, के खत्म होने का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी को एआईसीसी के चुनाव प्रबंधन विभाग का कर्ता-धर्ता नियुक्त करने का लैटर तो कई सप्ताह से तैयार है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 दिसंबर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव, संगठन प्रभारी (जीएसओ), केसी वेणुगोपाल ने कथित रूप से राहुल गांधी से अनुरोध किया है कि उन्हें ''मिशन केरल'' सौंपा जाए और 2019 से वे संगठन महासचिव की जो जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, उनसे उन्हें मुक्त किया जाए। जबकि यह सवाल खड़ा है कि क्या वेणुगोपाल, मई 2026 में होने वाले केरल चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद के
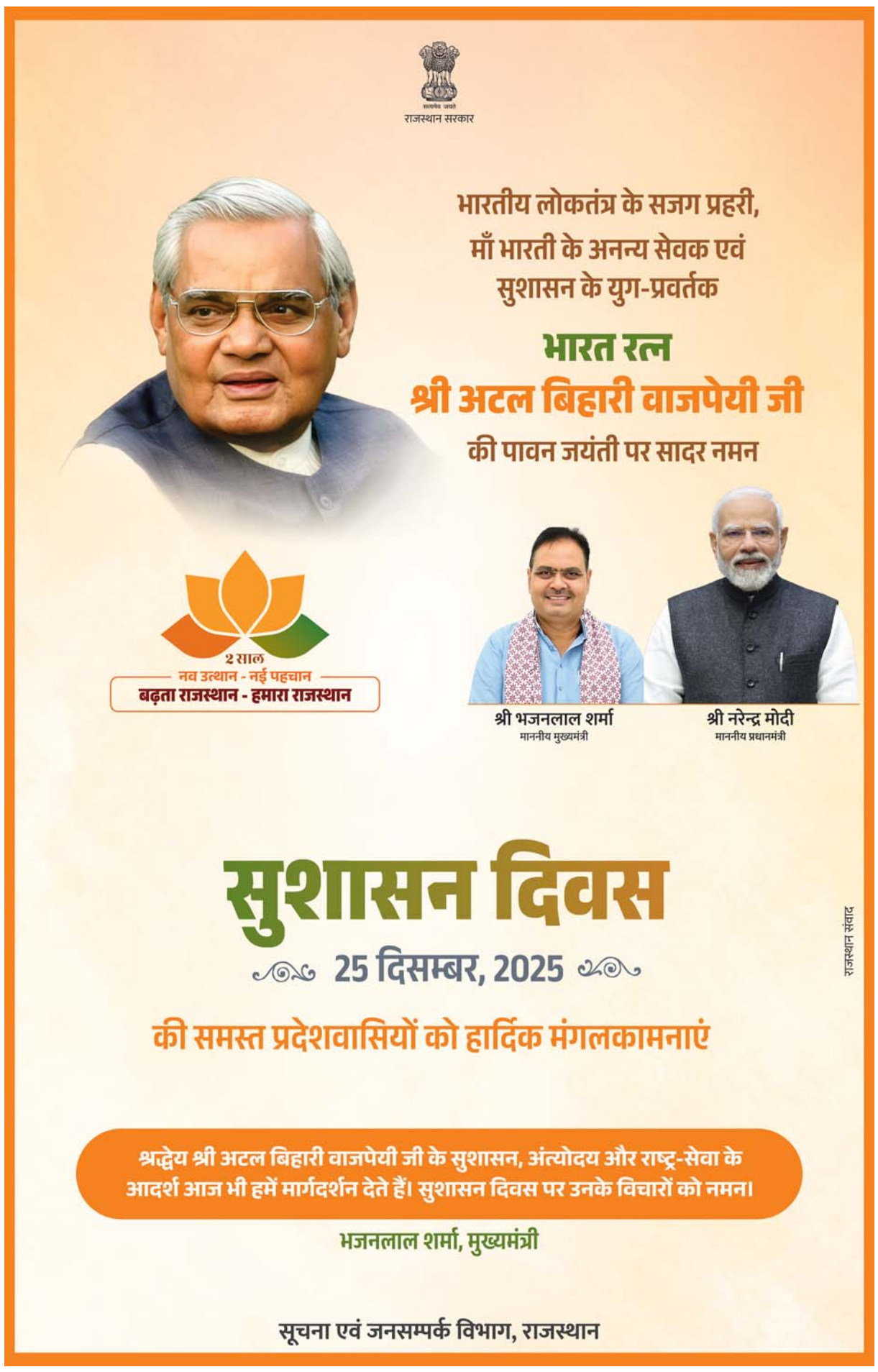
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)